Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

फरवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष चार राज्यों में शामिल 3
- बुलंदशहर-खुर्जा के 55 गाँव यीडा में शामिल 3
- पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत 4
- मुख्यमंत्री ने डी.जी. वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया 4
- कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिये एसजेवीएनएल ने उत्तर प्रदेश सरकार से एमओयू किया 5
- गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट सम्मानित 5
- वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 6
- युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित 6
- लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढाँचे का उद्घाटन 7
- यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट -2023 7
- उच्च शिक्षा मंत्री ने जी-20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया 8
- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आँवला और फूलपुर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया 8
- पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना 9
- टी.टी.एल. एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति 9
- उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग 10
- 'मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना' 11
- 'पूर्वांचल की शान 2023' में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियाँ सम्मानित 12
- लखनऊ में नवाबों की पाँच ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल 12
- उत्तर प्रदेश के 150 आईटीआई अपग्रेड होंगे 13
- बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI 14
- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी 14
- उत्तर प्रदेश में बनेगा हाई टेक मिलिट्री अस्पताल 15
- इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन 15
- उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति 15
- उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन 16

नोट :

उत्तर प्रदेश

75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष चार राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले चार राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने 'हर घर जल, 75 लाख नल'समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश में विभाग की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए 75 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा जल जीवन मिशन की दो साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म 'हर घर पानी, खुद निगरानी'का अनावरण व विभाग की उपलब्धियाँ गिनाती ई बुकलेट का विमोचन किया गया।
- कार्यक्रम में खासकर बुंदेलखंड में विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से गाँव-गाँव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया तथा पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुँचने से मिली खुशियों को सांस्कृतिक झलकियों से प्रस्तुत किया गया।
- जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 75,26,740 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1.58 करोड़ से अधिक, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ से अधिक और गुजरात 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्य हैं।

बुलंदशहर-खुर्जा के 55 गाँव यीडा में शामिल

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में शामिल हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा।
- यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा ज़िले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर ज़िले के 40 गाँव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे।
- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेलमार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिये प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के पास तक ले जाना था। इसके लिये प्राधिकरण ने 55 गाँवों को शामिल करने की योजना बनाई।

नोट :

पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के बी.एस.ए. रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएम श्री योजना से गोरखपुर ज़िले के 40 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये हर विद्यालय पर करीब दो-दो करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें एक माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल है।
- हर विकास खंड से दो-दो विद्यालयों का विभिन्न मानकों पर प्राप्तांक के आधार पर मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया जाएगा।
- गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग से सभी विकास खंडों से चार-चार स्कूलों की सूची तैयार कर भेजी गई है। बेसिक शिक्षा के कुल 80 स्कूलों में से 40 का चयन पीएम श्री के अंतर्गत करके उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।
- इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पैडागॉजी आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य संचालित होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) केंद्र सरकार की योजना है। इसमें देश के हर ब्लॉक से दो विद्यालयों का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में योजना को पाँच सालों के लिये (2022-2027) लागू किया गया है।
- रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न मानकों के आधार पर ज़िले में माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ एक विद्यालय एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज ही खरा उतरा है। पीएम श्री के लिये भेजी गई सूची में इस वजह से सिर्फ एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का ही नाम है।

मुख्यमंत्री ने डी.जी. वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया

चर्चा में क्यों ?

5 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डी.जी. वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल डी.जी. वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु

- जी-20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डी.जी. वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- यह डी.जी. वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्त्वपूर्ण डिजिटल नव पहलों- 'माई गॉव', 'डिजी लॉकर', 'ई-हॉस्पिटल', 'ई-नाम', 'जेम पोर्टल', 'यू.पी.आई.', 'उमंग', 'जी.एस.टी.एन.', 'साइबर सुरक्षित भारत', 'आरोग्य सेतु'आदि को दिखाएगी।
- इस वैन में वी.आर. सेटअप भी है, जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन, जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर भुगतान, डिजिलॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है।
- भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तहत खनन प्रबंधन के लिये 'माइन मित्रा' एवं अन्य तकनीकी अवसंरचनाओं का सृजन किया गया।
- इस वैन में 2 स्क्रीन, इंट्रैक्टिव क्विज के लिये हैं, जिस पर डिजिटल इंडिया व जी-20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते है।

नोट :

- इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिये, राज्य सरकार द्वारा 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के अंतर्गत 'डिजीशक्ति पोर्टल' के माध्यम से छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को नि:शुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन प्रदान किये जा चुके हैं।
- बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये प्रेरणा पोर्टल विकसित किया गया है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, 1090- विमेन पावर लाइन हेल्पलाइन को समुचित रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है।

कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिये एसजेवीएनएल ने उत्तर प्रदेश सरकार से एमओयू किया

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है।

प्रमुख बिंदु

- कंपनी ने प्लांट लगाने के लिये प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 एकड़ ज़मीन मांगी है। इस ज़मीन पर कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी।
- इस प्लांट के लगने से करीब 300 लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। वहीं, प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को लाभ होगा।
- एसजेवीएनएल के अतिरिक्त महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी जालौन के काल्पी और उरई तहसील में 75-75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है जिनमें काल्पी के परासन गाँव में स्थापित प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ गया है।
- वहीं, कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पॉवर प्लांट निर्माणाधीन है।
- उल्लेखनीय है कि सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किसी माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है।
- कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठनों को बिजली बेचने के लिये संपर्क करेगी।

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस परेड में कुल 52 गर्ल्स कैडेटों ने भाग लिया था। जिन्हें ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- परेड टुकड़ी में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन से 9 कैडेट, 19 बटालियन से 16 कैडेट, 63 बटालियन से 4 कैडेट, 64 बटालियन से 5 कैडेट, 67 बटालियन से 21 कैडेट, 39 से 8 कैडेट और 5 एयर स्क्वार्डन एनसीसी से 9 कैडेट शामिल थे।
- साथ ही सीनियर डिवीजन के एनसीसी लड़कों ने ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- वहीं लखनऊ एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की दो गर्ल्स कैडेटों को नेतृत्व, पहल, लगन और विभिन्न कैंपों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिये डायरेक्टर जनरल एनसीसी दिल्ली का प्रशंसा पत्र मेडल और रुपए 3000 का पुरस्कार दिया गया।
- डायरेक्टर जनरल एनसीसी का प्रशंसा पत्र सीनियर अंडर अफसर कीर्ति राय और सीनियर अंडर अफसर वैभवी भटे 67 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन को मिला है।
- विदित है कि 75 ज़िलों से आए कैडेटों के सम्मान में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वोच्च कलाकारों को 20 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन में मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया।

नोट :

वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को मिडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने केंद्र सरकार से की गई सिफारिश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से खाली हुए पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की जाए।
- उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्तूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किये गए थे। यहाँ के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होने के नाते इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
- न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर का जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। उन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से कानून में स्नातक किया है। 1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।
- वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध संघ, सीबीएसई और कई अन्य नगर निगमों के स्थायी वकील रहे हैं।
- उन्हें जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह सात साल के लिये मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल और पाँच साल के लिये स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्य थे।
- 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे पदोन्नत हुए। 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे।

युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोटरबाइक रेसर श्रेयश, विश्व रेस में क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय हैं।
- हाल ही में उन्होंने FIM MiniGP वर्ल्ड सीरीज के लिये क्वालीफाई किया है। श्रेयश भारत के पहले 'मिनी जीपी' चैंपियन भी हैं।
- युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को बचपन से बाइक चलाने का बहुत शौक रहा। उन्होंने केवल सात साल की उम्र से बाइक चलाना शुरू कर दिया था।
- मोटो जीपी (भारत) के आयोजक फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयश के पालन-पोषण का जिम्मा उठाया है।
- उल्लेखनीय है कि 10-12 फरवरी 2023 तक चलने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, उत्तर सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनेताओं को एक मंच पर लाता है।

नोट :

लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढाँचे का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी, 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढाँचे को और बेहतर बनाने के प्रयास के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुश्ती के लिये एक उन्नत हॉल तथा एक खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता (एनसीओई) केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहाँ पर भारत की विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- एनसीओई लखनऊ में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के साथ ही इसकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है और अब यहाँ किसी भी समय राष्ट्रीय शिविर में आने वाले खिलाड़ियों सहित 460 एथलीटों के रहने की क्षमता स्थापित हो गई है।
- नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा, जबकि 80 बिस्तरों के मौजूदा दो छात्रावास इस केंद्र में लड़कों के प्रशिक्षण के लिये आरक्षित रहेंगे।
- खेल चिकित्सा केंद्र को मौजूदा मेडिकल सेंटर से अपग्रेड किया गया है और अब इसमें खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ-साथ एक खेल मनोवैज्ञानिक भी होंगे।
- इस प्रांगण को पूरी तरह से सुसज्जित खेल विज्ञान केंद्र बनाने के लिये यहाँ पर उन्नत बायोमैकेनिक मशीनें लगाई जा रही हैं।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट -2023

चर्चा में क्यो ?

12 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (यूपी जीआईएस-2023) का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में कुल 33 लाख, 50 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19058 एमओयू साइन हुए। इससे करीब 93 लाख, 82 हज़ार, 607 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये 'निवेश सारथी' नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
- उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय यूपी जीआईएस-2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन ने बाराबंकी में 30 हज़ार की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है।
- यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में अस्पताल खोलने का एलान किया है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।
- उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिये 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ,उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिये इस मंच पर बुलाया जाता है।

नोट :

- उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की भागीदारी देखी गई।
- दिसंबर 2022 में यूपीजीआईएस 2023 के लिये राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किये थे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके।
- इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएँ 'साझेदार देश' रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें 28 हज़ार करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर एमओयू साइन किये गए थे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने जी-20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के होटल सेंट्रम, सुशांत गोल्ड सिटी, में आयोजित जी-20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों एवं संस्थानों के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं।
- प्रदर्शनी में राज्य सरकार के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन एवं संस्कृति, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहीं निजी संस्थाओं द्वारा भी अपने डिजिटल स्टॉल लगाए गए हैं।
- शिक्षा मंत्री ने मापल्स इंडिया द्वारा लोकेशन स्पेशल (जिसके माध्यम से लोकेशन प्राप्त की जाती है), सिविल-20 (जो स्वयं- सेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर शासन को मुहैया कराता है), मिलेंदराज द्वारा निर्मित खेती ड्रोन (जो 3 फिट की गहराई तक उर्वरकता की जानकारी मुहैया कराता है), माइटी द्वारा डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर (जिसमें डिजिटल प्लेटफार्म्स के द्वारा मानवीय अनुभवों को साझा किया जाता है) आदि के स्टॉलों पर जाकर बारीकी से अवलोकन किया तथा स्टाल संचालकों से विस्तार से उनके स्टॉल से संबंधित जानकारी एवं अनुभव भी प्राप्त किया।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आँवला और फूलपुर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आँवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको-आईएफएफसीओ) के नैनो यूरिया तरल (लिक्विड) संयंत्रों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा।
- केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। यह मिट्टी को खराब होने से बचाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाती है। इसलिये यह किसानों के लिये सबसे अच्छी है।

नोट :

- उन्होंने आगे कहा कि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह सामान्य (डीएपी) की जगह लेगी। नैनो-डीएपी से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह डीएपी से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगा।
- डॉ. मांडविया ने कहा कि यह एक वैकल्पिक उर्वरक है। सामान्य यूरिया का उपयोग करने पर केवल 35% नाइट्रोजन (यूरिया का ही) उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है और अप्रयुक्त यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादन स्थिर हो चुका है, इसलिये भी वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक था।

पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर का कुछ भाग तथा (ग्राम आटगढ़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रूदानखेड़ा, ग्राम विशुनपुर, ग्राम जिंदाना, ग्राम पाराभदराही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ) ग्राम व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हेक्टेयर (1033.082 एकड़) भूमि पर पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।
- इस भूमि को चिन्हित करते हुए इसमें से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि नि:शुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित/अधिग्रहण किया जाएगा।
- इस टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हिकेल (एस.पी.वी.) का गठन किया जाएगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये (पेडअप कैपिटल) की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार तथा 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा।
- स्पेशल पर्पज व्हिकेल का गठन कंपनी एक्ट-2013 के अंतर्गत होगा। एस.पी.वी. में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे।
- टेक्सटाइल पार्क हेतु एस.पी.वी. का गठन करके संबंधित भूमि एस.पी.वी. को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी।
- भारत सरकार के द्वारा दिये गए अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पी.पी.पी. मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

टी.टी.एल. एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को उत्तर-प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टी.टी.एल.) एवं राज्य सरकार (व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) के मध्य तैयार किये गए एम.ओ.ए. को हस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस एम.ओ.ए.के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टी.टी.एल.) के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किये जाने हेतु राज्य सरकार एवं टी.टी.एल. के मध्य एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया जाएगा। भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन/परिवर्धन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

नोट :

- इस एम.ओ.ए. के अनुसार टी.टी.एल का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का अंश जी.एस.टी सहित 713 करोड़ रुपए एवं प्रत्येक चयनित आई.टी.आई. में 10 हज़ार वर्गफीट बिल्ट-अप-स्पेस (कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि) निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए है।
- इस प्रकार परियोजना की कुल लागत (विभाग का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए प्लस टी.टी.एल. का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए) 5472.9668 करोड़ रुपए है।
- इस एम.ओ.ए. की अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्धारित है। हस्ताक्षरित किये जाने वाले एम.ओ.ए. में प्रथम 05 वर्ष एवं अगले 05 वर्ष की शर्तों तथा दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक् से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किये जाने पर तत्समय विचार किया जाएगा।
- इंडस्ट्री 4.0 प्रस्तावों की मांग के अनुसार टी.टी.एल. द्वारा 150 आई.टी.आई. में 11 दीर्घ अवधि के एवं 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
- टी.टी.एल. के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आई.टी.आई. में इन नवीन पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षकों एवं साथ ही साथ आई.टी.आई. में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को टी.टी.एल. की सहयोगी कंपनियों में ओ.जे.टी. (ऑन जॉब ट्रेनिंग) व डी.एस.टी. (डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग) करने का अवसर प्राप्त होगा तथा सफल प्रशिक्षार्थियों को टी.टी.एल. की सहयोगी कंपनियों एवं अन्य कंपनियों में अप्रेंटिसशिप/रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा।
- उन्नयन से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 12 से 15 हज़ार अभ्यर्थी तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 हज़ार अर्थात कुल लगभग 35 हज़ार अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे।

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

17 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बिजली बैंकिंग के तहत सर्दियों तथा सामान्य दिनों में जब राज्य में बिजली की मांग औसत अथवा कम रहती है, उस समय कॉरपोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बिजली जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर ज़रूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा।
- गौरतलब है कि 2014 में राज्य में महज़ 1 करोड़ 42 लाख 64 हज़ार बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गए हैं। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग, जो 12327 मेगावाट थी, वह 2022 में दोगुने से अधिक 26589 मेगावाट पहुँच गई है। बिजली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई है। ज़िला मुख्यालय तथा उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, गाँवों को भी 6 घंटे अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही है।
- उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने से निवेशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नज़र आ रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में तेज इजाफा होगा।
- माना जा रहा है कि दो से तीन साल के अंदर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पहुँच जाएगी। हालाँकि उद्योगों के आने के साथ ही पावर कॉरपोरेशन को आने वाले सालों में बिजली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सिरे से करना होगा, जिसकी तैयारी कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है।
- कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के मुताबिक बिजली बैंकिंग के बड़े फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन सर्दियों व आम दिनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों से करार हो रहा है, उन्हें दे देगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से 29 मिलियन यूनिट, तमिलनाडु से 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया है। कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान ने पिछले वर्ष 449.6 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब चार गुना अधिक 1967.8 मिलियन यूनिट की बैंकिंग का करार किया है। मध्य प्रदेश से भी बैंकिंग का करार हुआ है।
- चेयरमैन का दावा है कि इस प्रयास से प्रदेश में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में जब मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली चली जाएगी। बिजली बैंकिंग के तहत कॉरपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे।
- इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में जून से सितंबर के बीच बिजली की मांग अधिकतम होती है उस समय भी बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज से 12 रुपए और अधिक की दर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पावर एक्सचेंज में बिजली का रेट बहुत अधिक रहता है।
- चेयरमैन ने बताया कि 7413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों से बिजली का उत्पादन 2025-26 तक शुरू हो जाएगा। 2023-24 के अंत तक इसमें से 5000 मेगावाट की इकाइयाँ चलने लगेंगी।
- 2021-22 में 927 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में अब तक 91 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा चुकी है। 2030 तक राज्य में बिजली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता 40392 मेगावाट तक की जानी है। 2023 में अनुबंधित उत्पादन क्षमता 32356 मेगावाट तक ले जाने की है।
- 2022-23 में बिजली की अधिकतम मांग 26589 मेगावाट तक पहुँची जबकि 2014 में अधिकतम मांग 12327 मेगावाट ही थी। 2023-24 में अधिकतम मांग 27776 मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है।

'मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना'

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 'मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना' शुरू करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना'के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किये जाने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिये दिये जाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, इनमें से 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय हैं।
- शहरों में कालोनियों के साथ ही कुछ मार्गों को बनाने की जिम्मेदारी निकायों के पास है। निकायों के पास सड़क सुधार योजना और केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से पैसा प्राप्त होता है, लेकिन अतिरिक्त मद नहीं है। इसीलिये नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना' नाम से अलग मद बनाना चाहते हैं, जिससे शहरों में लोगों को ज़रूरत के आधार पर सड़क की सुविधाएँ दी जा सकें।
- उच्च स्तर से सहमति के बाद नगर विकास विभाग ने नए बजट में इसके लिये प्रावधान करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें तर्क दिया गया है कि शहरी सड़कें प्रदेश के विकास का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं।
- सड़कों को गड्डा मुक्त किया जाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिये नाली के साथ सड़क की सुविधा देना ज़रूरी है। इसीलिये एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना' की शुरुआत की जाएगी।
- इसके अलावा निकायों में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिये इस योजना में अतिरिक्त पैसे दिये जाएंगे। उदाहरण के लिये निकाय जितना हाउस टैक्स वसूलेंगे, उसका 50 फीसदी अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। नगर विकास विभाग का मानना है कि इससे निकायों में हाउस टैक्स वसूली की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में बढ़ोतरी होगी।

नोट :

'पूर्वांचल की शान 2023' में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियाँ सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से एक होटल में आयोजित 'पूर्वांचल की शान 2023' सम्मान समारोह में शान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है।
- उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ काशी तो दूसरी तरफ प्रयागराज संगम नगरी है। कबीर भी अंतिम दिनों में पूर्वांचल पहुँचे। गोरखपुर में गोरक्षनाथ की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी प्रदेश का अपना अलग ही योगदान है।
- इनका हुआ सम्मान -
  - वाराणसी - शिक्षाविद प्रो. राम मोहन पाठक।
  - भदोही - कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी।
  - गाजीपुर - यूथ रूरल एंटरप्रोन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया।
  - मिर्जापुर - विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज व सत्यम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जय प्रकाश मौर्या।
  - जौनपुर - मॉडर्न वीर रेज सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसीडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, कुमुद गिरीश हास्पिटल प्रा. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. क्षितिज कुमार शर्मा और ईशा हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉ. रजनीश श्रीवास्तव।
  - गोरखपुर - बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. गनेश कुमार, टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी, डीपी मोटर्स के नितिन मतनहेलिया।
  - कुशीनगर - गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक ओपी गुप्ता व कृष्णा हास्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. संजय गुप्ता।

लखनऊ में नवाबों की पाँच ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल

चर्चा में क्यों ?

21 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व विभाग की निदेशक डॉ. रेणु द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शहर की पाँच ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक डॉ. रेणु द्विवेदी ने बताया कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद पर्यटन विभाग ने इन्हें असंरक्षित श्रेणी में डालते हुए यहाँ हेरिटज होटल विकसित करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। इन इमारतों को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और इनके हेरिटेज होटल बनने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा।
- माना जा रहा है कि इन इमारतों को होटल का लुक देने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन विभाग की आय में भी इज़ाफा होगा। राजस्थान में इसी तरह से तमाम ऐतिहासिक इमारतों को होटलों में बदलने का बड़ा फायदा हुआ है। तेजी से पर्यटक इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं।
- निदेशक डॉ. रेणु द्विवेदी ने बताया कि फिलहाल लखनऊ की छतर मंजिल, रोशन-उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्ताने-इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहद बख्स को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी है।
- उन्होंने बताया कि इन इमारतों को असंरक्षित किये जाने के मामले में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विभाग में आपत्ति दर्ज करा सकता है और केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के एक माह के भीतर आएंगी।

नोट :

- डॉ. रेणु द्विवेदी ने बताया कि अन्य राज्यों में इमारतों को होटलों में बदलने के इस मॉडल ने विरासत को बचाने में काफी मदद की है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इससे इन स्मारकों को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाने में भी मदद मिलेगी।
- इन ऐतिहासिक इमारतों का व्यावसायिक उपयोग के लिये परिवर्तन करने से इनके संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। राज्य एएसआई यह सुनिश्चित करेगा कि इमारत का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण विरासत को प्रभावित किये बिना किया जाए।
- पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर इन भवनों को हेरिटेज होटलों में बदलने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही इससे राज्य की राजधानी में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- छतर मंजिल भवन - इस भवन का निर्माण नवाब सआदत अली खाँ ने 1798-1814 के बीच अपनी माता छतर कुँअर के नाम पर करवाया था। इसके बाद बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के 1827-1837 के शासनकाल में इस भवन को सँवारा गया। छतर मंजिल का भवन इंडो-इटालियन स्थापत्य कला से बना है। इसके भूतल की दीवारों से गोमती का पानी टकराता था, जिससे भवन में बराबर ठंडक बनी रहती थी। इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिये किया जाता था। यह भी माना जाता है कि सिंहासनारोहण के समय जब नवाब ने छत्र धारण किया तब उसने इस महल के ऊपर भी छत्र लगवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छतर मंजिल का प्रयोग क्रांतिकारियों ने किया।
- गुलिस्तान-ए-इरम - इसका निर्माण 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। यह नसीरुद्दीन का निजी पुस्तकालय था। ब्रिटिश काल में यह सरकार का फार्म हाउस बन गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने कैसरबाग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, क्योंकि यह नवाबों का गढ़ था। इसी आदेश के तहत गुलिस्तान-ए-इरम को भी ध्वस्त कर दिया गया।
- कोठी दर्शन विलास - कोठी दर्शन विलास के जिस भवन में अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है, वह कभी एक महल था। इसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में शुरू हुआ।
- रोशन-उद्-दौला - अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर (1827-1837) के शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री रोशन-उद्-दौला ने इसका निर्माण कराया। इसे जल्द ही नवाब वाजिद अली शाह ने ले लिया। इसके वास्तु में ब्रिटिश और मुगल कला दोनों के संकेत मिलते हैं।
- फरहत बख्श कोठी - इस कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था। इसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने सन् 1781 में करवाया था। यह इंडो-फ्रेंच वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह उनका निवास स्थान हुआ करता था।

उत्तर प्रदेश के 150 आईटीआई अपग्रेड होंगे

चर्चा में क्यों ?

21 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने जा रही है। अपग्रेडिंग के लिये 150 आईटीआई को चिह्नित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हज़ारों युवाओं को लाभ होगा और वो मौजूदा इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल और रोज़गार हासिल कर सकेंगे।
- विदित है कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संचालित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के कुल 72 व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे हैं।
- इंड्रस्ट्री 0 प्रस्तावों की मांग के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता बताई गई है। आधुनिक बाज़ार के मांग के अनुरूप ऐसे नवीन व्यवसायों/पाठयक्रमों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता से स्थानीय/राष्ट्रीय /वैश्विक औद्योगिक मांग के अनुरूप दक्ष मैन पावर तैयार किया जा सके। टाटा टेक्नोलॉजी लि.(टीटीएल) के इस प्रस्ताव को शासन की ओर से मंजूरी दी गई है।
- इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी लि. एवं राज्य सरकार (व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) के बीच इसी संबंध में एक एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) भी किया गया है।
- कौशल विकास मिशन के डिप्टी डायरेक्टर राजीव यादव ने बताया कि इस एमओए के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जिन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा, उसमें आने वाले व्यय का 13 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि 87 प्रतिशत हिस्सा निजी कंपनी टीटीएल द्वारा उठाया जाएगा।

नोट :

बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी डॉ. वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था।
- गौरतलब है कि डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के नाम से 250 से ज्यादा पेटेंट दवाएँ भी हैं।
- डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव-सह-वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पिछले महीने डीसीजीआई के पद के लिये उनके नाम की सिफारिश की थी। इसको संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल समिति ने आदेश पारित किया है।
- विदित है कि डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख पद होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लीनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण के लिये वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिये समग्र विकास करने हेतु फिल्म नीति लागू की है।
- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिये राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी।
- फिल्म निर्माण के लिये कुल शूटिंग दिवस के दो तिहाई दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- नोएडा में एक हज़ार एकड़ में फिल्मसिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना है। फिल्मसिटी में बनने वाली फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी।
- फिल्म नीति के तहत ये सुविधाएँ भी मिलेंगी -
- शूटिंग के लिये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह की व्यवस्था की जाएगी। विभागों के स्तर से आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी किया जाएगा।
- आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल में कमरे के किराए पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी।
- प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के लिये निर्माण पर 50 फीसदी, हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कुल शूटिंग दिवस के कम से कम 50 फीसदी यूपी में शूटिंग होने पर एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।
- वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख या एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म में पाँच मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

नोट :

उत्तर प्रदेश में बनेगा हाई टेक मिलिट्री अस्पताल

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होगा।

प्रमुख बिंदु

- मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण करने का उद्देश्य देश की सेवा में जुटे सैनिकों, सैन्य परिवार के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
- उल्लेखनीय है कि करीब एक दशक पूर्व मध्य कमान की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री अस्पताल की आवश्यकता जताई गई थी। वर्ष 2011-2012 में इसके लिये एक प्रस्ताव भी बनाया गया था।
- वर्ष 2012-2013 में यह प्रस्ताव पहले मध्य कमान और उसके बाद रक्षा मंत्रालय भेजा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने मेरठ में रक्षा भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल के निर्माण के साथ राजधानी लखनऊ में भी अत्याधुनिक मिलिट्री अस्पताल को मंजूरी दे दी है, जो मध्य कमान का सबसे बड़ा मिलिट्री अस्पताल होगा।
- मेरठ में यह मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण 379 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह अस्पताल 545 बेड का होगा।
- मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल के लिये सेना ने मेरठ के भगत चौक से औघड़नाथ मंदिर के बीच ज़मीन पूर्व से ही चिह्नित कर रखी है। सेना की ओर से प्रस्तावित जमीन पर पूर्व में ही 'साइट फॉर एमएच'का बोर्ड लगा दिया गया था। इस नए मिलिट्री अस्पताल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 ज़िलों के सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह लोगों को ट्रॉमा सेटर पहुँचाया जाए, जहाँ उनका बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में दूसरे इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स के आयोजन के लिये इजराइल से पाँच सदस्यीय चिकित्सकीय टीम बुलाई गई है।
- उन्होंने बताया कि आयोजन से पहले टीम के सदस्यों ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के इलाज, जाँच आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आपदा के समय बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के उद्देश्य से शुरू ट्रॉमा कोर्स में 39 जीटीसी के जवान, एनडीआरएफ, पुलिस, पीएसी जवान, आरपीएफ, सीआरपीएफ के चयनित जवान प्रशिक्षण लेंगे।
- आयोजन में इजराइल में रैमबैम एचसीसी के निदेशक प्रोफेसर माईकल (मिकी) हाल्बरथल व उनकी टीम के अन्य सदस्यों समेत एम्स नई दिल्ली के ट्रॉमा सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमित गुप्ता द्वारा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में आग्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी (एएनएम), जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) और पैरामेडिकल कोर्स में अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा। इसके लिये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नई नीति बना रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति पर कॉलेज के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से सलाह मांगी गई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एएनएम की 19,220 व जीएनएम की 18,323 सीटें हैं। पैरामेडिकल के विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में करीब 20 हजार से अधिक सीटें हैं। अभी तक इनमें दाखिला कॉलेज प्रबंधन करता था, परंतु अब कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं ले पाएंगे।
- दरअसल वर्ष 2023-24 से केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत छात्रों को कोर्सवार आवेदन करना होगा, इसमें वरिष्ठता क्रम में कॉलेज का नाम भरना होगा।
- उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आने वाले आवेदनों में न्यूनतम योग्यता व इंटरमीडिएट में मिले नंबरों के हिसाब से राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी, फिर काउंसिलिंग के जरिये कॉलेज अलॉट होंगे।
- फैकल्टी के सचिव प्रो. आलोक कुमार के मुताबिक अभी तक यह आरोप लगता था कि कॉलेजों की मिलीभगत से कम मेरिट वाले छात्रों को मनचाहे कोर्स और कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। परंतु इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और मेधावी छात्रों के साथ न्याय होगा।

उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गाँव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर नितिन गडकरी ने बलिया-आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड स्पर रोड के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की भी घोषणा की।
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल साढ़े चार घंटे में पहुँचा जा सकेगा। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा एक घंटे में और बलिया से पटना डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सकता है।
- उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
- इस एक्सप्रेस-वे से बलिया के किसानों की सब्जियाँ लखनऊ, वाराणसी और पटना की मंडियों में आसानी से पहुँच सकेंगी। सब्जी उत्पादक किसानों को वाराणसी, गाजीपुर और हल्दिया के तीन मल्टी मॉडल टर्मिनल का सीधा लाभ मिलेगा।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनेगा। यह सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर ज़िले को दिल्ली-कोलकाता जी.टी. रोड से जोड़ेगी।
- इसी तरह सैदपुर से मरदह तक सड़क बनेगा, जिससे सैदपुर होते हुए मऊ से वाराणसी का सीधा संपर्क हो जाएगा।
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आजमगढ़ ज़िले के पिछड़े इलाकों को भी नया कनेक्टिविटी मिलेगा।

नोट :